



भारतीय लोकतंत्र में बुनकर समाज की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

गोविन्द सोनकर

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।



सारांश :

इस पेपर का मुख्य उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र में बुनकर समाज की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करने से है। समकालीन समय में विश्व के सबसे बड़े एवं सफल लोकतंत्र में बुनकर समाज के राजनीतिक स्थिति, हासिएकरण एवं मनोदशा के ऊपर भी फोकस किया गया है।

संकेत शब्द : लोकतंत्र, बुनकर समाज, राजनीतिक शासन व्यवस्था, मूल्य, अधिकार, हासिएकरण।

परिचय :

लोकतंत्रीय शासन प्रणाली, अपनी उत्पत्ति के समय से ही एक सर्वाधिक लोकप्रिय राजनीतिक शासन-व्यवस्था रही है। समकालीन समय में देखा जाय तो आज इक्सवी शताब्दी में विश्व के अधिकांश देशों की राजनीतिक व्यवस्था, लोकतंत्रीय-मूल्यों पर आधारित हैं। किसी भी समाज में प्रजातान्त्रिक शासन-व्यवस्था को वास्तविक धरातल पर तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता, जब तक की किसी समाज के हासिएकरण पर रहने वाले शेष अंतिम व्यक्ति तक इसके मूल्यों एवं अधिकारों की पहुंच सुनिश्चित न हों।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाय तो आज भारत, विश्व का सबसे बड़ा एवं सफल लोकतान्त्रिक देश हैं, हालांकि १९४७ के आजादी के पश्चात जब राजनैतिक-वर्ग द्वारा स्वतन्त्र भारत में लोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्था को अपनाने का निर्णय लिया गया, तब प्रजातंत्र के अनेक विशेषज्ञों एवं विद्वानों ने इस निर्णय की खुले दिल से आलोचना की, परन्तु सात दशकों की भारतीय लोकतंत्र की शासन-व्यवस्था की यात्रा अपने आप में रोचक रहीं हैं। समकालीन समय में, हमारे सामने सबसे अहम् प्रश्न यह है कि क्या जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु भारतीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? क्या सचमुच उन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह सफल हो पाया है? क्या भारतीय लोकतंत्र, समाज के प्रत्येक वर्ग, तबके, समुदाय एवं अंतिम शेष व्यक्ति तक पहुंच पाया है या फिर एक कोरी कल्पना बनकर रह गया है?

इन प्रश्नों का जब हम सटीक एवं यथार्थ उत्तर ढूँढ़ने का प्रयास करते हैं तो यह पाते हैं कि कुछ हद तक यह सफल भी हुआ है एवं कुछ हद तक असफल भी हुआ है। परन्तु इस सन्दर्भ में इस पेपर का दृष्टिकोण भारतीय लोकतंत्र के अन्तर्गत बुनकर समाज की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का संक्षिप्त अवलोकन करने का प्रयास किया गया है।

अपने अध्ययन एवं फील्ड सर्वेक्षण के दौरान हमें यह देखने को मिला है कि बुनकर समाज जो कि आज भी इक्सवी शताब्दी एवं वैश्वीकरण के दौर में विकास की मुख्य धारा से हटकर कोसों दूर हासियेकरण पर रहकर अपना गुजर-बसर कर रहा है एवं भारतीय लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा से बिल्कुल बाहर है। समकालीन समय में बुनकर समाज की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय एवं चिंतनीय है। यद्यपि राज्य एवं केन्द्र सरकार दोनों के द्वारा बुनकर समाज के कल्याण एवं उन्नति के लिए अनेकों नीतियों एवं कानूनों को बनाया गया है परन्तु सच्चाई यह है कि सरकार के द्वारा बनाये गये नीतियों का लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान समय में बुनकर समाज के लोगों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति में जो बढ़ोतरी हुई है इसका मुलभूत कारण भी यही है कि सरकारी नीतियों का फायदा जिनको मिलना चाहिए उनको ना मिलकर इसका लाभ केवल इस ब्यवसाय से जुड़े बड़े मिल् मालिकों बिचौलियों, मध्यस्थों एवं कम्पनी एजेंटों को ही मिल पा रहा है। राजनीतिक जागरूकता एवं उदासीनता का अभाव होने के कारण एवं राजनीतिक नेताओं के ध्यान न देने के कारण आज बुनकर समाज निम्न स्तर का जीवन जीने को विवश है। उचित मार्केटिंग ब्यवस्था न होने के कारण इन्हें अपने प्राइवट का सही एवं वाजिब हक एवं मूल्य भी नहीं मिल पाता है। विधान सभा एवं लोकसभा में इनका अपना प्रतिनिधि न होने के कारण इनकी समस्याओं को पुरजोर तरीके एवं सलीके से नहीं उठाया जाता है, जिसके कारण यह ब्यवसाय आज पहले की तुलना में बहुत ही पिछड़ गया है जो कि कभी लाखों लोगो का ब्यवसाय हुआ करता था।

सही एवं सच्चे अर्थों में भारतीय लोकतंत्र अपने वास्तविक रूप को तभी धारण कर सकता है, जब यह अपने अन्दर समाज के सभी लोगो का समावेश कर सके एवं सभी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ सके नहीं तो यह एक कोरी कल्पना बनकर रह जायेगा। बुनकर समाज भी इसी लोकतंत्रीय शासन-व्यवस्था का एक अहम् हिस्सा है इन्हें अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़कर लेनी होगी, तभी इनका विकास हो सकता है अन्यथा नहीं।

कालीन का इतिहास :

आज से लगभग २४०० वर्ष पहले सेंटपीटर्स वर्ग के हर्मिटाज म्यूजियम में विश्व की पहली कालीन पाई गयी थी। यह भी कहा जाता है कि अलेक्जेंडर जनरल सेलुकास ने अपनी बेटी की शादी में चन्द्रगुप्त मौर्य को आज से लगभग ३२० बी सी पहले एक गलीचा उपहार में उनको दिया था। इस समारोह के उपरांत इसका प्रसार विश्व के अन्य जगहों जैसे एशिया, सीरिया, बेबीलोन, कांधार एवं ईरान में हुआ।

भारत में कालीन की बुनाई बहुत ही प्राचीन समय से की जा रही है यह एक ऐसा ब्यवसाय है जो कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में लाखों लोगो के आजीविका का मुख्य संसाधन है। भारत, विश्व का एक ऐसा प्रजातांत्रिक देश है जो कि अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विविधता के लिए सम्पूर्ण संसार में लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध है, और सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ का हथकरघा उद्योग एवं कालीन पुरे विश्व में प्रसिद्ध है। यद्यपि भारत में कालीन कि बुनाई का काम सोलहवीं शताब्दी में प्रारम्भ किया गया, जब यहाँ पर मुगल साम्राज्य का शासन था। महान सम्राट अकबर के शासन काल में पर्शिया से कुछ बुनकरों को कालीन की बुनाई करने हेतु भारत लाया गया जिसका विवरण हमें अकबर के शासन काल में रहें दरबारी कवि अबुल फजल के “आईने अकबरी” में देखने को मिलता है। कालीन जिसे की ‘गलीचा’ के नाम से भी जाना जाता है।

कालीन बुनाई के उपकरण एवं डिज़ाइन :

कालीन की बुनाई प्रायः हाथों एवं मशीनों दोनों माध्यमों से की जाती है। इसकी बुनाई करने में कैची, पंजा, वूल, छुरा, ए हेअवी क्रवेड एंड वुड का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में मशीनों के माध्यम से भी इसकी बुनाई की जा रही है, परन्तु यह बहुत ही खर्चीली है। बाज़ार में अनेको तरह की कालीन देखने को मिलती है, जो कि अलग-अलग डिज़ाइन में उपलब्ध है, उनमें से कुछ प्रमुख रूप से जैसे एंटिक पर्शियन डिज़ाइन, वेस्टर्न डिज़ाइन, स्पेशल डिज़ाइन, चाँद-चौथाई डिज़ाइन एवं साधारण डिज़ाइन है। ये सभी डिज़ाइन पर्शिया से भारत में लायी गयी है।

उत्पादन के प्रमुख केन्द्र :

भारत में कालीन बुनाई के प्रमुख केन्द्र के रूप में पूर्वी उत्तरप्रदेश का भदोही, मिर्जापुर एवं वाराणसी जिला पुरे विश्व में काफी लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध है। यह भी कहा जाता है कि ये कालीन बुनाई के सबसे पुराने केंद्र हैं। इसके अलावा उत्तर-प्रदेश के आजमगढ़, सोनभद्र, इलाहाबाद एवं जौनपुर जिले में भी कालीन की बुनाई की जाति हैं।

इसके अतिरिक्त भारत के अन्य भागों में जैसे कि बिहार में समस्तीपुर, गया, ओबरा एवं मधुबनी, जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर, अनन्तनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवारा एवं पुलवामा, आसाम, पाण्डिचेरी, पश्चिम-बंगाल में दार्जिलिंग, महाराष्ट्र में नागपुर, पंजाब में अमृतसर कर्नाटक में मंगलौर, तमिलनाडू में मद्रास एवं वालजपेट, हिमाचल-प्रदेश में धर्मशाला एवं डलहौजी, मध्य-प्रदेश में ग्वालियर, हरियाणा में पानीपत, राजस्थान में जयपुर, अलवर, टोंक, बीकानेर एवं बाड़मेर, आंध्र-प्रदेश में वारंगल एवं इल्लूर और लद्दाख में लेह कालीन बुनाई के केंद्र स्थित हैं।

मुख्य निर्यातक देश :

समकालीन समय में भारत, विश्व का दुसरा सबसे बड़ा गलीचा या कालीन का निर्यातक देश हैं, वही संसार में ईरान का प्रथम स्थान हैं। उत्तर-प्रदेश के भदोही एवं मिर्जापुर, दो ऐसे जिले हैं, जहां कि अस्सी प्रतिशत कालीनो का विश्व के विभिन्न भागों में निर्यात कर दिया जाता हैं। भारत के पूर्वी उत्तर- प्रदेश एवं विभिन्न भागों में तैयार किये गए कालीनों के प्रमुख निर्यातक देशों में क्रमशः जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया, स्विट्ज़रलैंड एवं ग्रेट-ब्रिटेन हैं।

महत्व एवं उपयोग :

वर्तमान समय में कालीनों का महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा हैं। विशेष रूप से इसका उपयोग घरों को सजाने एवं एक आरामदायक वस्तु के रूप में किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग सिनेमा हालो, पुस्तकालय, आधुनिक व्यायामशाला, संसद भवन, शादी समारोह, सेमिनार रूमों, अवार्ड समारोहों, घरों के बहार एवं अन्दर एक अस्थैतिक सुन्दरता प्रदान करने के लिए किया जा रहा हैं। रूम को गर्म एवं लक्जरी बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता हैं।

बुनकर समाज की स्थिति :

समकालीन समय में भारतीय लोकतान्त्रिक देश में बुनकर समाज की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति काफी दयनीय एवं चिंतनीय हैं। कालीनों की बुनाई करने वालो को समाज में हेय की दृष्टि से देखा जाता हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कालीन की बुनाई का काम प्रायः समाज के कमजोर एवं दीनहीन लोग ही करते हैं, जिनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हैं। परन्तु सच्चाई यह भी है कि इस पेशा से समाज के संभ्रांत एवं शक्तिशाली लोग भी जुड़े हुए हैं जिन्हें मिल् मालिक एजेंट, बिचौलिए एवं लूम ओनर्स कहा जाता हैं। भारतीय प्रजातंत्र में बुनकर समाज एक उपाश्रित वर्ग का जीवन जीने को विवश हैं। राज्य के द्वारा बनाये गये कल्याणकारी नीतियों का लाभ इन्हें नहीं मिल पाता हैं, प्रायः ऐसा देखा गया हैं कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा समय-समय पर बहुत सारी नीतियां बुनकर समाज के कल्याण के लिए बनाई गयी हैं, परन्तु सच्चाई इसके बहुत ही विपरीत हैं। इन नीतियों का लाभ इस व्यवसाय से जुड़े मिल् मालिक कम्पनी एजेंट्स, बिचौलिए एवं बड़े-बड़े लूम मालिको को ही मिल पाता है, क्योंकि राजनीतिक रूप से ये लोग काफी सक्रिय एवं जागरूक हैं एवं बैंक अधिकारियों से इनके व्यक्तिगत सम्बन्ध बहुत ही अच्छे हैं।

आर्थिक दुर्दशा के मूलभूत कारण एवं समाधान

भारतीय समाज में बुनकर समाज के आर्थिक दुर्दशा के पीछे निम्नलिखित कारण हैं जिनका समाधान होना अति आवश्यक है।

1. भारतीय प्रजातंत्र में बुनकर समाज के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण यह है कि इन्हें अपने प्राइवट का सही एवं उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि उपयुक्त बाजार की व्यवस्था न होने के कारण इन्हें अपने प्राइवट की सही कीमत नहीं मिल पाती है।
2. इस पेशा से जुड़े लोगों में राजनीतिक उदासीनता एवं जागरूकता की कमी होने के कारण इनका शोषण कम्पन्नी एजेंट, बिचौलिये, साहूकार एवं मिल मालिकों के द्वारा आसानी से किया जा रहा है।
3. अंतरराष्ट्रीय मार्केट एवं वैश्विक बाजार में कालीनों की कीमत बहुत ही अधिक है परन्तु इसमें काम करने वाले लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया है कि इसमें काम करने वाले लोग ठेकेदारी के रूप में काम करते हैं और इन्हें अपने प्राइवट को बेचने हेतु मिल मालिकों एवं लूम ओनर्स के ऊपर आत्मनिर्भर रहना पड़ता है जो कि इनका शोषण करते रहते हैं।
4. बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी भी बुनकर समाज का शोषण आसानी से करते रहते हैं क्योंकि बैंक इन्हें लोन आसानी से नहीं देता है, बैंक लोन के लिए इन्हें एक मोटी रकम रिश्वत के रूप में बैंक मनेजर्स को देना पड़ता है तभी इन्हें लोन मिलता है अन्यथा नहीं।
5. साहूकारों के द्वारा भी इनका शोषण किया जाता है, क्योंकि साहूकारों के द्वारा लिया गया पैसा सही समय पर नहीं चुकता करने पर ब्याज के रूप में मोटी रकम इन्हें अदा करनी पड़ती है।
6. इनका अपना ट्रेड यूनियन न होने के कारण इनकी समस्याओं को उठाने वाला भी कोई नहीं है जिसके कारण बुनकर समाज एक उपाश्रित वर्ग का शिकार है। बुनकर समाज के लोगों को अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी अन्यथा इन्हें हासिएकरण पर रह कर ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा।
7. चुनाव के समय विभिन्न क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय दल केवल वोट लेने के समय ही इनकी समस्याओं को पुरजोर तरीके एवं सलीके से उठाते हैं। चुनावी माहौल में बुनकर समाज को ऐसे राजनीतिक दलों से सावधान रहते हुए वोट करनी चाहिए। उन्हें उसी दल को अपना मत देना चाहिए जो सही में बुनकरों का कल्याण कर सके।
8. शिक्षा जो कि किसी भी समाज के विकास एवं उत्थान के लिए रामबाण है, बुनकर समाज शैक्षणिक रूप से भी काफी पिछड़ा हुआ है। अधिकांश लोग शिक्षा से वंचित हैं, जिसके कारण ये विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं।
9. बुनकरों का संसद एवं विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व न होने के कारण ये अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से नहीं उठा पाते हैं। अतः बुनकर समाज के सशक्तिकरण, उन्नति एवं कल्याण हेतु लोकसभा एवं विधानसभा में इनका प्रतिनिधी होना अतिआवश्यक है। जिससे कि ये अपनी आवश्यकताओं एवं मांगों को सरकार के समक्ष आसानी से रख सके एवं मनवा सके और अपने हित में गवर्नमेंट पॉलिसी को बनवा सके।
10. वर्तमान समय में कालीन उद्योग, बाल बंधुआ मजदूरी से भी ग्रसित है जिसे समाप्त करने हेतु रुगमार्क, स्टेप, कालीन, केयर & फेयर (RUGMARK, STEP, CARE & FAIR), बंधुआ मुक्ति मोर्चा इत्यादि संस्थाएँ इस दिशा में साकारात्मक रूप से काम कर रही हैं।
11. समकालीन समय में लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था में बुनकरों की राजनीतिक हिस्सेदारी में कमी देखने को मिलती है जिसके कारण भी ये लोग आज के वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के दौर में भी उपाश्रित वर्ग का जीवन जीने के लिए विवश है। अतः इन्हें लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था में अपने हक की लड़ाई खुद लड़कर लेनी पड़ेगी। किसी और के सहारे इनका विकास सम्भव नहीं हो सकता है।

निष्कर्ष:

उपरोक्त विवेचनों एवं विश्लेषणों से स्पष्ट होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय प्रजातंत्र के आर्थिक विकास में बुनकर समाज का अपना महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे इन्कार नहीं किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा के संचयन में भी इनका अपना उल्लेखनीय योगदान है। परन्तु सच्चाई यह भी है कि जहाँ एक तरफ इस व्यवसाय से जुड़े कमजोर तबकों एवं समुदायों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक स्थिति काफी दयनीय है। वहीं दूसरी तरफ इस पेशा से जुड़े मिल मालिकों, कपन्नी एजेंट, साहूकारों एवं मध्यस्थों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति इनसे काफी अच्छी है। अतः एक ऐसी प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए जो कि समाज के हर कमजोर, दीनहीन, असहाय एवं उपाश्रित वर्ग को लोकतान्त्रिक मूल्यों, अधिकारों एवं विकास की मुख्य धारा से जोड़ सके, बुनकर समाज भी इसी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिनको कि विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाना अति आवश्यक है, नहीं तो प्रजातंत्र अपने वास्तविक अर्थों से करोड़ों मील दूर चला जायेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ:

1. शर्मा, अलख. एन, राजीव शर्मा एवं निखिल राज. (२००४). 'चाइल्ड लेबर इन कारपेट इंडस्ट्री, इम्पैक्ट ऑफ़ सोशल लबेलिंग इन इन्डिया' नई-दिल्ली, इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट पृष्ठ संख्या ४८ - ८६ .
2. सिंह, आर. के. एवं आर. के. राम. (१९८९). 'सेन्सस ऑफ़ इन्डिया, उत्तर-प्रदेश हैंडीक्राफ्ट सर्वे रिपोर्ट, भदोही ब्लूलेन कार्पेट इंडस्ट्री, पार्ट- एकस सी, सीरीज-22. पृष्ठ संख्या १-३३.
3. सक्सेना, एस. सी. एवं बी. के. वर्मा. वी. के. भार्गवा. (१९८९). 'हैंडीक्राफ्ट सर्वे रिपोर्ट, कार्पेट क्रफ्ट ऑफ़ ओबरा विलेज, बिहार, पार्ट- एकस डी, सीरीज-4. पृष्ठ संख्या १-३६.
4. रवि, अपर्णा. (मार्च ३१- अप्रैल ६, २००१). 'कोम्बटिंग चाइल्ड लेबर विथ लेबल्स, केस ऑफ़ रुगमार्क. इकोनोमिक एवं पॉलिटिकली वीकली. वॉल्यूम नं ३६. नं.१३. पृष्ठ संख्या- ११४१-११४७.
5. टकर, ली. (२००६). 'चाइल्ड स्लेव्स इन माडर्न इन्डिया' नई-दिल्ली, द जॉन होपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस, २३ - ३६.
6. श्रीवास्तव, रवि. एस. & निखिल. राज. (२०००). 'चिल्ड्रेन ऑफ़ कारपेट लूम, ए स्टडी ऑफ़ होम बेस्ड प्रोडक्शन ऑफ़ कारपेट इन उत्तर-प्रदेश' एन एल आई रिसर्च स्टडीज सीरीज नं. ०११/२०००, पृष्ठ संख्या ५४.
7. भान, आर. के. (१९३८). 'इकोनोमिक सर्वे ऑफ़ कार्पेट इंडस्ट्री इन कश्मीर'. श्रीनगर. वॉल्यूम नं. 2. पृष्ठ संख्या 1-21.
8. गोस्वामी, के. के. (२०१३). 'प्रासेस कंट्रोल इन कार्पेट मैन्युफैक्चरिंग नई-दिल्ली. अभिषेक पब्लिकेशन. पृष्ठ संख्या- 11-17.
9. गोस्वामी, प्रोपा. (२०१५). 'परफॉरमेंस मेज़रमेंट ऑफ़ हैण्डमेड कार्पेट इंडस्ट्री' नई-दिल्ली, अभिषेक पब्लिकेशन. पृष्ठ संख्या- 11-31.
10. गोस्वामी, के. के. (२००९). 'एडवांसेज इन कार्पेट मैन्युफैक्चरिंग. नई-दिल्ली. वूडहेड पब्लिकेशन लिमिटेड. पृष्ठ संख्या- १३८-२६७.